Tc.No.: GUJHIN00722

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 58, शुक्रवार, 23 मार्च 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

सार समाचार

फतेहपुर में पत्नी से झगड़ युवक ने फांसी लगाकर दी जान

फतेहपुर (एजेंसी)। दो दिन पूर्व ही परदेश से कमा कर लौटे एक युवक का बुधवार देर शाम पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नाराज युवक रात में घर से निकल गया। सुबह पड़ोस के गांव में स्थित एक आम के बाग में उसका शव फांसी से झूलता मिलने से परिजनों में कोहराम मचा रहा। हथगाम थाना क्षेत्र के हरिरामपुर कैथोला गांव का रहने वाला उमेश परदेश में रहकर कमाता था। परिजनों ने बताया कि दो पहले ही उमेश परदेश से लौटा था। बुधवार की शाम को किसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। देर रात उमेश घर से निकल गया और घर नहीं लौटा। गुरुवार सुबह पड़ोस के गांव लालदासपुर गांव के ग्रामीणों ने जंगल जाते समय नहर के पास आम के बाग में एक शव को फांसी के फंदे से झूलता देखा। यह देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। किसी ग्रामीण ने शव की शिनाख्त उमेश के रूप में की और परिजनों को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

जापानी पार्क में मिला युवक का शव मृतक की उम्र लगभग 30 साल

नई दिल्ली (एजेंसी)। रोहिणी जिले के थाना प्रशांत विहार इलाके में एक अज्ञात युवक का शव जापानी पार्क से बरामद हुआ है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। फ्लिहाल पुलिस मृतक की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस को मृतक के पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जिससे उसकी पहचान हो सके। मृत युवक उम्र लगभग 30 साल है। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस आसपास के थानों में संपर्क कर रही है।सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बुधवार की सुबह सूचना मिली की जपानी पार्क के पास खाली पड़े हिस्से में किसी युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव देखने के बाद अनुमान लगाया कि, हो सकता है शव को कहीं और से लाकर वहां फेंका गया है। युवक का शव फूला हुआ था और काला पड़ चुका था, जिससे युवक की जहर से मौत होने का अंदेशा है। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और खून भी निकला था। शव के साथ कम्बल भी मिला है। आशंका है कि शव कम्बल में लपेटकर फेंका गया हो। युवक की कलाई पर एक घड़ी भी बंधी है, इससे पता चलता है कि हत्या करने वाले का इरादा लूटपाट नहीं था। पुलिस जांच में जुटी है।

पार्षदों ने बैठक में उठाया सुपर सकर मशीन खरीद का मामला

पूर्वी दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी निगम के पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति की बैठक में 4.5 करोड़ रपए में सुपर सकर मशीन की खरीद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने कहा कि मशीन की कीमत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन परियोजना के प्रस्ताव के तहत इतनी अधिक राशि का जिक्र किया गया है। पार्षद संजय गोयल ने कहा कि शहरी विकास फंड के तहत पूर्वी निगम को केन्द्र सरकार से सौ करोड़ रपए मिलने हैं। इसके लिए विभिन्न मशीनों की खरीद और ढांचागत विकास की योजना बनाई है। इसके तहत ठोस कचरे के निपटान के लिए कई मशीनों की खरीद के साथ ही दो सुपर सकर मशीनें खरीदी जानी हैं। इन मशीनों की मदद से बंद नालों की गाद की गहराई से गाद की सफाई में उपयोग होता है। मशीन के लिए दर्शाई गई कीमत को लेकर संजय गोयल समेत कई पार्षदों ने सवाल उठाए। गोयल ने कहा कि एक मशीन की कीमत 4.71 करोड़ रपए से ज्यादा बताई गई है, जो कि अनुचित प्रतीत हो रही है।

बुजुर्ग दंपति समेत तीन को बुरी तरह पीटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अलीपुर थाना इलाके में एक बदमाश ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर दबंगई दिखाते हुए इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से एक बुजुर्ग दम्पति समेत तीन लोगों की लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और

मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मामले की सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। मौके से पुलिस ने सभी घायलों को ले जाकर राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। नरेला निवासी कैलाश कुमार झा ने बताया कि, शाम के समय पड़ोस में रहने वाला एक युवक एक बुजुर्ग दंपति को बुरी तरह से पीट रहा था।

संसद गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिलेंगे केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल विभिन्न राजनीति दलों के नेताओं से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे और लोकसभा में अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण पिछले 14 दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित रहने के संबंध में जारी गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि वह कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, तेलुगू देशम पार्टी और टीआरएस समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के यहां जायेंगे और उन्हें विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिये मनायेंगे क्योंकि इसके कारण पांच मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में एक दिन भी काम नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वह संसद में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते रहे हैं और अब वह उनके घर जाकर मिलेंगे और उनसे चर्चा शुरू करने का आग्रह करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 23 दिनों का है और उसमें से 14 दिन कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा के लिये है और सरकार नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। मोदी सरकार ईमानदारी से शासन चला रही है । मेघवाल ने कहा कि जब तक संसद में व्यवस्था नहीं हो, शोर शराबा खत्म नहीं हो, तब तक स्पीकर के लिये भी अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को आगे बढ़ाना कठिन होता है। कहा कि सरकार अपने खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने को तैयार है और उसे लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संसद में चर्चा करने की बजाए टेलीविजन पर चर्चा करने में क्यों व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कार्यवाही चलाने में काफी धन खर्च होता है और ऐसे में सदस्यों को सदन में चर्चा करनी चाहिए । गोयल ने

सिल्ट डम्पिंग सेंटर पर गाद डालने का विरोध, महापौर धरने पर

पूर्वी दिल्ली। गीता कॉलोनी स्थित एसडीएम ऑफिस के पास सिल्ट डम्पिंग सेंटर साइट पर बुधवार को निगम अधिकारियों ने तीन ट्रक गाद व मलबा डाल दिया। जैसे ही इसकी खबर आसपास के लोगों को लगी तो लोग वहां पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। इतना ही नहीं जिस मार्ग से ट्रक डम्पिंग साइट के अंदर जा रहे थे, उसको बंद कर लोग धरने पर बैठ और निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही महापौर नीमा भगत भी मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ धरने पर बैठ गई। स्थिति को बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गीता कॉलोनी स्थित एसडीएम ऑफिस के पास 11 एकड़ जमीन पर निगम द्वारा गाद डम्पिंग साइट बनाई जा रही है। इस सेन्टर पर पूर्वी दिल्ली से निकलने वाली गाद को यहां एकत्र कर बाद में इसे रिसाइकल किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार सुबह गाद व मलबे से भरे निगम के तीन ट्रकों ने यहां पर इसे डाल दिया। इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग यहां पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। खबर मिलते ही महापौर नीमा भगत भी मौके पर पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों के साथ धरने पर बैठ गई। उनका कहना था कि उन्होंने डम्पिंग साइट यहां नहीं बनाने के लिए उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा, ताकि इसके बनने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि यह उपराज्यपाल के आदेश पर ही डीडीए ने गीता कॉलोनी स्थित एसडीएम कार्यालय के पास 11 एकड़ जमीन अस्थायी तौर पर दो साल के लिए निगम को दी है, ताकि मॉनसून के दौरान नालों से निकलने वाली गाद यहां डाली जा सके। इस डम्पिंग साइट के विरोध में आसपास के आरडब्ल्यूए व क्षेत्रीय लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से उनका इस इलाके में रहना दुश्वार हो जाएगा। इस मामले को लेकर एक तरफ निगम के अधिकारी अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर नालों से निकलने वाली गाद को यहां पर डालेंगे, वहीं दूसरी ओर महापौर भी इसको लेकर तीखे तेवर अपनाए हुए हैं।

पुलिस बल तैनात11 एकड़ जमीन अस्थायी तौर पर दो साल के लिए डीडीए ने निगम को दी है

आधार से वास्तविक लोगों की पहचान होगी और फर्जी पैनकार्ड की समस्याएं खत्म होंगी: केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। 'आधार' का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए वास्तविक लोगों की पहचान में मदद मिलेगी और फर्जी पैनकार्ड जैसी समस्याएं खत्म होंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियां भी इससे दूर होंगी।

केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ को बताया कि 'आधार' से न सिर्फ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद और पारदर्शिता भी आएगी। पीठ के समक्ष दिए गए नोट में सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से जरूरतमंदों तक सरकारी लाभ पहुंचने में देरी होती है और इसकी गति धीमी हो जाती है। वेणुगोपाल ने कहा, 'मेरे मुताबिक, सभी स्तर पर अगर लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो कुछ भी सफल नहीं होगा। कई देश जिन्हें भारत के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई वे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार के जरिए लाभ पाने वाले परिवारों द्वारा इसे दाग के तौर पर नहीं देखा जाता है। नोट में कहा गया, 'इसलिए, योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लक्षित करने की प्रक्रिया सुधारने और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसकी जरूरत महसूस की गई। आधार की परिकल्पना मूलत: उपरोक्त दोनों समस्याओं के जवाब और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफल रूप से लागू करने के लिए की गई थी।'

केंद्र ने राजीव गांधी को उद्धृत किया

केंद्र की एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 'आधार' योजना का बचाव करते हुए अपनी दलीलों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि यह जनता के धन का लीकेज रोकेगी। अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने संविधान पीठ के समक्ष बहस शुरू करते हुए कहा, 'इस देश के

एक पूर्व प्रधानमंत्री (स्व. राजीव गांधी) ने तो रिकॉर्ड पर यह कहा था कि समाज के निचले तबके के कल्याण के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही वास्तव में उन लोगों तक पहुंचते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि 'आधार' होने पर इस क्षेत्र की अनेक गड़बड़ियों पर काबू पाया जा सकता है।

पेंशन के लिए 'आधार' पर कोर्ट का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन निकालने के लिए 'आधार' के अनिवार्य प्रयोग पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी पहचान पर कोई संदेह नहीं है। संविधान पीठ ने जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने हक से वंचित नहीं हो। पीठ ने कहा कि पेंशन खाते सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होते हैं और इसलिए इसमें किसी गलत पहचान का सवाल नहीं उठता।

»» सीबीएसई शुरू करेगा 50 से अधिक वोकेशनल कोर्स

इलेक्टिव सब्जेक्ट में फेल होने पर जुड़ जाएंगे एडिशनल वोकेशनल कोर्स के मार्क्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सत्र 2018-19 से अलग-अलग क्षेत्रों में 50 से भी अधिक वोकेशनल कोर्स शुरू करेगा। इसमें 15 कोर्स नौवीं और दसवीं के स्तर पर व 40 कोर्स सीनियर सेकेंडरी यानि कक्षा 11वीं और 12वीं के स्तर पर शुरू होंगे। इन कोसरे में रिटेल, मीडिया, एग्रीकल्चर, सिक्यूरिटी, हेल्थकेयर, आईटी, टैक्सेशन, फैशन, डिजाइशन और फूड एंड न्यूट्रीशन जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। बोर्ड के एक परिपत्र के मुताबिक सेकेंडरी स्तर पर वोकेशनल कोर्स को पांच अकादमिक विषयों के साथ ही अतिरिक्त छठे विषय के रूप में ऑफर किया जाएगा। वहीं यदि कोई विद्यार्थी तीन इलेक्टिव विषयों (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक में फेल हो जाता है तो उस विषय को

वोकेशनल कोर्स अतिरिक्त विषय के रूप में किए जाएंगे चयनित

वोकेशनल विषय से रिप्लेस कर दिया जाएगा और कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम पांच बेहतर विषयों के परिणाम के आधार पर तैयार किया जाएगा। हालांकि यदि छात्र फेल विषय की परीक्षा फिर से देना चाहता है तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। ठीक इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी लेवल पर छात्र वोकेशनल प्रोग्राम को चुन सकते हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वे नये सत्र से एक या उससे अधिक वोकेशनल कोर्स में ऑफर करना शुरू करें। इनमें से कई कोसरे को पेशेवर संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को बताया है कि वोकेशनल पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये जरूरी सहयोग और शिक्षक प्रशिक्षण भी समय-समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

बोर्ड में वोकेशनल एंड ट्रेनिंग निदेशक बिस्वजीत साहा की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि सेकेंडरी स्तर के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में लिखित और प्रायोगित परीक्षा के समान अंक निर्धारित होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कुछ के लिए लिखित और प्रायोगिक का अनुपात 60 व 40 तथा कुछ में 70 व 30 होगा। परिपत्र में बोर्ड ने कहा है कि इन पाठ्यक्रमों को नई पीढ़ी में कौशल और दक्षता बढ़ाने व उनमें रोजगार के विकल्पों को लेकर जागरूकता पैदा करने के मद्देनजर शुरू किया गया है। बोर्ड को उम्मीद है कि इससे शिक्षा समग्र, सार्थक और कौशल उन्मुखी बनेगी।

दिल्ली के स्टूडेंट्स किन विषयों में है फिसड्डी

नई दिल्ली। आज एक तरफ जहां देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी छात्रों के प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। ये बात हम नहीं बल्कि एनसीईआरटी की तरफ से किए गए सर्वे से सामने आयी है।

अंग्रेजी, गणित में दिल्ली के छात्र फिसड्डी शिक्षा को लेकर दिल्ली देश के पांच सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में शामिल है जबकि आठवीं के स्टूडेंट्स की अंग्रेजी के मामले में तो स्थिति और भी बदतर है। नेशनल एचिवमेंट सर्वे (एनएएस) के मुताबिक, पिछले साल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की तरफ से किए गए सर्वे में पता चला कि तीसरी कक्षा के स्टूडेंट्स गणित के मामले में फिसड्डी राज्यों में दूसरे नंबर पर है। यह सर्वे अन्य एजेंसियों की तरफ से कराए गए अन्य इसी तरह के उन सर्वे को बल देता है जिसमें राजधानी समेत देशभर में शिक्षा की व्यवस्था की स्थिति को दयनीय बताया है। दिल्ली में सिर्फ आठवीं कक्षा पर किए गए सर्वे में सिर्फ 32 फीसदी ही अंग्रेजी भाषा के सवालों का सही जवाब दे पाए जबकि सिर्फ 34 फीसदी बच्चे गणित का ठीक ठीक जवाब दिया। राजधानी में जब तीसरी कक्षा के छात्रों का सर्वे किया गया तो सिर्फ 54 फीसदी बच्चों ने गणित के पूछे गए सवालों का सही जवाब दिया जबकि 58 फीसदी बच्चों ने अंग्रेजी का सही उत्तर बताया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन स्थित डिफेंस कॉलोनी के सी ब्लॉक में 6 संपत्तियां सील की गई हैं।

पूर्वी दिल्ली के त्रिवेणी अपार्टमेंट में तोड़फोड़ के दौरान हंगामा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीलिंग को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी के साथ दिल्ली सरकार की सर्वदलीय बैठक के बावजूद बुधवार को भी राजधानी में सीलिंग जारी रही। अलग-अलग इलाकों में कुल 33 संपत्तियां सील की गई। सबसे अधिक संपत्तियां उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सील की गई। पूर्वी दिल्ली स्थित विवेक विहार के त्रिवेणी अपार्टमेंट में नगर निगम के दस्ते ने तोड़फोड़ की। जिससे वहां जबरदस्त हंगामा हुआ।

आरोप है कि अपार्टमेंट के अन्दर जमीन के टुकड़े पर अतिक्रमण कर रखा था। नगर निगम का दस्ता सुबह उत्तरी दिल्ली के करोलबाग इलाके में पहुंचा और सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। करोलबाग जोन के राजौरी गार्डन एवं ईस्ट पंजाबी बाग में कुल 11 संपत्तियां सील कर दीं। सिटी सदर-पहाड़गंज में 7 संपत्तियां सील की गई हैं। सभी संपत्तियां स्टिल्ट पार्किंग के दुरुपयोग के चलते सील की गई हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन स्थित डिफेंस कॉलोनी के सी ब्लॉक में 6 संपत्तियां सील की गई हैं। इसके साथ ही वेस्ट जोन वेस्ट पंजाबी बाग में दो संपत्तियां स्टिल्ट पार्किंग के दुरुपयोग के चलते सील की गई हैं। पूर्वी दिल्ली में कुल 7 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें अनधिकृत निर्माण के चलते तोड़फोड़ करने वाली दो संपत्तियां भी शामिल हैं।

कारोबारी को मारा चाकू

नई दिल्ली (एजेंसी)। लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में कारोबारी के निगम में दी शिकायत वापस लेने से इनकार पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। वारदात के वक्त पीड़ित बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल संजय गुप्ता (30) को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। केस दर्ज कर पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक संजय गुप्ता फतेहपुरी की गांधी गली में रहते हैं और लाहौरी गेट मार्केट में उनका मसालों का कारोबार है। पिछले साल अगस्त में उसने एक जमीन खरीदी थी। नवम्बर कुछ दबंगों ने उस संपत्ति पर कब्जा कर अवैध निर्माण शरू कर दिया। अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की खबर मिलते ही पीड़ित ने मामले की शिकायत निगम और थाने में की और अवैध निर्माण रुक गया।

भारतीयों की मौत की खबर

ईराक में लापता 39 भारतीयों की मौत की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल है। मृतकों के परिजनों पर क्या बीत रही होगी, इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हालांकि यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार पिछले चार सालों से उनका पता करने के लिए तत्पर नहीं थी। जिस आइएस जैसे बर्बर आतंकवादी संगठन के हाथों वे पड़ गए थे, उसमें उनके बचने की उम्मीद कम ही थी। बावजूद इसके सरकार ने यदि उनको मृत घोषित नहीं किया तो इसका कारण यही था कि उनके बारे में कोई भी सूचना कहीं से नहीं मिल पाई थी। आइएस ने इराक के जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था वहां तक किसी सरकार का पहुंचना असंभव था। जब इराक की सेना और प्रशासन की वहां उपस्थिति नहीं थी तो फिर हमारे लिए पता करने का स्रेत क्या हो सकता था? उस पूरे क्षेत्र में आइएस के आतंक का राज कायम था। सरकार की बातों पर विास करें तो जितने स्रेतों से संभव था जानकारी लेने की कोशिश की गई और अपुष्ट सूचना यह थी कि शायद उन लोगों को कैदी बनाकर रखा गया हो। यह बात अलग है कि उनमें से जान बचाकर भाग आए हरजीत मसीह का दावा है कि उसने अपने सामने इनको मारे जाते देखा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कह रहीं हैं कि हरजीत की कहानी मनगढ़ंत थी। किंतु वह झूठ क्यों बोलेगा इसका कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिलता। आइएस की क्रूरता के जो दृश्य हमारे सामने आए हैं, उनके आलोक में केवल कल्पना की जा सकती है कि हमारे बंधुओं के साथ उसने कैसा व्यवहार किया होगा? स्वराज के बयान से इतना तो साफ है कि मोसूल में आइएस की पराजय के बाद से सरकार ने उनका पता करने के लिए जो कुछ संभव था किया और इराक सरकार के सहयोग से उनका पता भी चल गया। हालांकि विपक्ष को कम-से-कम कुछ मिनट के लिए शांत होकर सुषमा स्वराज को लोक सभा में अपनी बात रखने देना चाहिए था। उसके बाद उन्हें जितना विरोध करना होता करते। इससे संदेश यह गया है कि हमारे सांसदों में ऐसे भी लोग हैं, जो इतने संवेदनशील मसले पर भी अपनी संकुचित राजनीति से बाहर नहीं आ सकते। इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपको सरकार को दोषी ठहराना है तो ठहराइए लेकिन विदेश मंत्री की बात सुनने के बाद राज्य सभा की तरह ही लोक सभा में उन अभागे लोगों को श्रद्धांजलि तो दी जानी चाहिए थी। इससे उनके परिवारजनों को भी सांत्वना मिलती और देश में अच्छा संदेश जाता।

अनुसूचित जाति/जनजाति

सारे मामलों की गहराई से देख-परख के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के दुरुपयोग को रोकने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत के फैसले में पिछले तीस साल के दौरान इस एक्ट के मनमाफिक इस्तेमाल को लेकर चिंता ज्यादा गहरी थी। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। मसलन; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2016 में देशभर में जातिसूचक गाली-गलौच के 11,060 शिकायतें दर्ज हुई। जांच में 935 झूठी पाई गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले में आया है। जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफइस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। जांच में मामला झूठा पाया गया। इस मामले में बचाव पक्ष का कहना है कि अगर अनुसूचित जाति के खिलाफ ईमानदार टिप्पणी करना अपराध हो जाएगा तो इससे काम करना कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है कि अदालत पर कानून के दुरुपयोग और निदरेष को बचाने का दारोमदार था। और अदालत का इस कानून को लेकर जारी फैसला इसकी पुष्टि भी करता है। हालांकि देखना होगा कि इस फैसले की आड़ में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों पर ज्यादती न होने लगे। क्योंकि अभी भी देश भर में इनके खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा और बेवजह की मारपीट की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। इसके साथ ही अदालत के जरिये ही अन्य कठोर कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा की जरूरत है, जो वर्तमान समय में दमनकारी प्रकृति की ज्यादा हैं। ध्यान देने वाली एक और बात है। राजनीतिक दलों में इस तरह के कानून और उसके कदम-कदम पर बेजा इस्तेमाल के लिए समझ और सहमति बढ़ानी होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट को लागू करने के पीछे भी सरकार का यही उद्देश्य था। लंबे समय से हो रहे दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सर्वोच्च अदालत के फैसले को एक अवधि बाद परखने की भी जरूरत होगी। सो, नियमों का बेहतर और पारदर्शी तरीके से पालन कराना निहायत जरूरी है।

सत्संग

''व्यक्त''

जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक आवश्यक रूप से जानने योग्य वस्तु है आत्मा। आत्मज्ञान ही वह अमूल्य निधि है जिसे पाकर जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है आत्मज्ञान की प्राप्ति। परन्तु आज सर्वथा इसके विपरीत हो रहा है। ध्यान उस तय की ओर आकर्षित किया जा रहा है, जिसको सर्वथा भुला दिया जाना चाहिए या उपेक्षित कर देना चाहिए। क्षणिक विषय वासनाओं का सुख, लोभ, मोह, लालच को उपेक्षित किया जाना चाहिए, पर आत्मसत्ता को उपेक्षित किया जा रहा है। समझा यह जा रहा है कि मनुष्य जो कुछ है, वह शरीर और मन तक ही सीमित है। इससे आगे, इससे ऊपर भी कुछ है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। भोग अपने चरम अवस्था में है। भौतिक रूप में जो वस्तुएं दिख रही हैं, उसे आखरी सत्य माना जा रहा है। वैसे तो अक्सर सुना जाता है कि हमारे शरीर और मन से ऊपर आत्मा है। सत्संग और स्वाध्याय आदि अवसरों पर आए दिन आंखों और कानों के पदरे पर यह शब्द टकराते रहते हैं। पर वह सब एक ऐसी विडम्बना बनकर रह जाता है, जो मानो कहने-सुनने और पढ़ने-लिखने के लिए ही खड़ी की गई हो, वास्तविकता से जिसका कोई सीधा संबंध न हो। यदि ऐसा न होता तो आत्मा को सचमुच ही महत्त्वपूर्ण माना गया होता। कम-से-कम शरीर, मन जितने स्तर का भी समझ गया होता तो उसके लिए उतना श्रम एवं चिन्तन नियोजित तो किया ही गया होता जितना कायिक, मानसिक उपलब्धियों के लिए किया जाता है। यथार्थता यह है कि आत्मा के संबंध में बढ़-चढ़कर बातें कहने-सुनने में प्रवीण होने पर भी उस संबंध में एक प्रकार से अपरिचित ही बने हुए हैं। यदि ऐसा न होता तो दिनचर्या में आत्मिक उन्नति के लिए कुछ स्थान नियत रहा होता। श्रम और मनोयोग में उसके लिए भी जगह होती। उपलब्धियों और धन को जिन प्रयोजनों में खर्च किया जाता है, उनमें एक मद आत्मविकास के लिए भी रखी गई होती। पर देखा जाता है कि इस संबंध में सर्वत्र घोर उपेक्षा ही संव्याप्त है। जिस प्रकार शरीर और मन को महत्त्व दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी आत्मज्ञान, आत्मानुभूति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य जीवन रूपी सुर दुर्लभ अवसर इसीलिए प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर तक सीमित न रहे, आत्मा की ओर भी बढ़े और उसका ज्ञान प्राप्त करे।

बजट सत्र

स्थगन के संदेश के साथ सभापति और अध्यक्ष संसद की कार्यवाही को शुरू करते हैं। क्या विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है? इस प्रश्न के जवाब के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और स्थगन के फैसले की प्रवृतियों का विश्लेषण जरूरी है। राज्य सभा में सभापति के रूप में वेंकैया नायडू ने पहली बार 11 अगस्त 2018 को सदन की कार्यवाही को संचालित किया। 11 अगस्त को राज्य सभा के 243वें सत्र का आखिरी दिन था। यह सत्र 19 दिनों तक चला था। इसके बाद राज्य सभा का 244 वां सत्र सभापति वेंकैया नायडू के नेतृत्व में 15 दिसम्बर से 5 जनवरी के बीच 13 दिनों तक चला। 245वां सत्र बजट सत्र है, जो कि सबसे लंबा सत्र होता है। यह सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था।

सतीश पेडणोकर

सभा और राज्य सभा की 5 मार्च के बाद बजट सत्र की कार्यवाही जिस तरह से स्थगित हो रही है, उससे यह आशंका मजबूत हो रही है कि अगले चुनाव के पूर्व तक होने वाले संसद के सत्रों की यही स्थिति हो सकती है। स्थगन के संदेश के साथ सभापति और अध्यक्ष संसद की कार्यवाही को शुरू करते हैं। क्या विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है? इस प्रश्न के जवाब के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और स्थगन के फैसले की प्रवृतियों का विश्लेषण जरूरी है। राज्य सभा में सभापति के रूप में वेंकैया नायडू ने पहली बार 11 अगस्त 2018 को सदन की कार्यवाही को संचालित किया। 11 अगस्त को राज्य सभा के 243वें सत्र का आखिरी दिन था। यह सत्र 19 दिनों तक चला था। इसके बाद राज्य सभा का 244 वां सत्र सभापति वेंकैया नायडू के नेतृत्व में 15 दिसम्बर से 5 जनवरी के बीच 13 दिनों तक चला। 245वां सत्र बजट सत्र है, जो कि सबसे लंबा सत्र होता है। यह सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था लेकिन 9 फरवरी तक चलने के बाद 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 मार्च के बाद से लगातार सदन की कार्यवाही स्थगन की स्थिति में चल रही है। राज्य सभा में कार्यवाही को स्थगित करने के सभापति के फैसले ऐतहासिक माने जा रहे हैं। स्थगन के फैसलों की प्रवृति को इन तयों के आलोक में समझा जा सकता है। 5 मार्च के बाद से 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति द्वारा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। इस बीच में केवल दो दिन 6 मार्च और 15 मार्च को 2 बजे के बाद भी सत्र चला। अन्यथा दो बजे के लिए स्थगित की गई कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। 6 मार्च को 2 बजे सदन में सभापति के बजाय उप सभापति सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आए। उन्होंने कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति देखकर 3.30 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 15 मार्च को भी उपसभापति ने 3 बजे तक के लिए स्थगित किया। उप सभापति 2 बजे के बाद इन दो दिनों में लगातार ये प्रयास करते रहे कि सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगन के बाद दोबारा बैठे और सदन चलने का एक मौका और दें। उप सभापति और सभापति द्वारा कार्यवाही के स्थगन की प्रवृत्ति ये जाहिर करती है कि सभा की कार्यवाही को चलाने के लगातार प्रयास करने की दिशा में दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है। न केवल दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है बल्कि लोक सभा में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही को स्थगित करने के फैसले पर भी नजर डालें तो इस दृष्टिकोण के फर्क को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है। यही नहीं यदि 244 वें सत्र के दौरान सभापति के रूप में वेंकैया नायडू ने जिस तरह से सभा को संचालित किया, वह दृष्टिकोण 245वें सत्र में 5 मार्च के बाद बदला हुआ दिखता है। 5 मार्च के बाद से राज्य सभा में 11 बजे से कार्यवाही के शुरू होने के बाद सभापति दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं, जबकि 12 बजे से राज्य सभा में प्रश्नकाल शुरू होता है। सभापति के रूप में नायडू के मार्गदर्शन में 13 दिनों तक चले 244 वें सत्र में ही केवल दो दिन 11 बजे के बाद 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था। पहला 21 दिसम्बर 2017 को किया गया। उस दिन राज्य सभा में प्रश्नकाल के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी सुनिश्चित थी और सदन में गुजरात चुनाव के दौरान मनमोहन सिंह के खिलाफ पाकिस्तान के साथ साजिश करने के आरोप पर सदस्य सफाई देने की मांग कर रहे थे। 22 दिसम्बर को शुक्रवार था और उस दिन सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक चलती है। लिहाजा उस दिन सदन में कार्यवाही चलाने के लिए सहमति बनाने पर जोर दिया गया और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्य सभा के इतिहास में यह आमतौर पर देखा जाता है कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद यदि कार्यवाही को स्थगित करने के हालात पैदा होते हैं तो वह पहले दौर में 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे प्रश्नकाल होने की वजह से वे सदस्य भी सदन चलाने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जिनके प्रश्न पर सरकार का जवाब मिलना निश्चित होता है। लोक सभा में ही प्रश्नकाल 11 बजे से होता है । राज्य सभा में प्रश्नकाल का समय 12 बजे से करने का फैसला हामिद अंसारी ने अपने कार्यकाल में लिया था। 16वीं लोक सभा के 14वें सत्र में 5 मार्च से 11 दिन लोक सभा की कार्यवाही पहले 11 बजे प्रश्नकाल के लिए शुरू हुई और उसके बाद 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल को सदन की कार्यवाही में सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ज्यादा-से-ज्यादा सदस्यों के बहस में हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए जब सदस्य नरेश अग्रवाल ने प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग की तब सभापति नायडू ने प्रश्नकाल के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। लेकिन 5 मार्च के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के फैसले के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। यह 16 मार्च 2018 को ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आया। 16 मार्च को सदन में कार्यवाही के शुरू होने के बाद किसी तरह का विरोध नहीं था। लेकिन सभापति नायडू ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने का फैसला सुना दिया। उन्होंने कार्यवाही को स्थगित करने के फैसले के साथ कहा कि विपक्ष केवल बैंक घोटाले पर पर चर्चा की मांग कर रहा है। बैंक में घोटाले पर ही चर्चा के बजाय बैंकों में हुए सभी घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। 5 मार्च को जब सदन दोबारा बैठी तब देश का राजनीतिक तापमान इस रूप में परिवर्तित दिखाई दिया कि नरेन्द्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में 11 हजार करोड़ से ज्यादा की पीएनबी में हेराफेरी की बड़ी घटना सामने आ चुकी थी। ऐसा महूसस होता है कि दोनों सदनों की कार्यवाही 5 मार्च के बाद कार्यवाही के स्थगित करने के संदेश देने के लिए शुरू होती है। खासतौर से राज्य सभा में तो सदन को चलाने का प्रहसन भी दिखाई नहीं देता है। सदन के स्थगित होने के पीछे जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि अगले लोक सभा चुनाव से पहले संसद के होने वाले सत्रों में भी यही स्थिति हो सकती है। इसीलिए सदन की कार्यवाही को चलाने में परंपराओं से बेमेल और विद्रुप स्थितियां लगातार बढ़ रही है।

चलते चलते

शुभ लग्न-मुहुर्त

दिल्ली खुश हो तो भी मुश्किल और दिल्ली नाराज हो तो भी मुश्किल। दिल्ली में चाहे बारात निकलें या अर्थी निकलें, जाम तो लगना ही होता है। हालांकि अभी तक होता यह आया था कि बारात का दिन तो निश्चित ही होता है। पर अर्थी का नहीं होता। जबकि शायर ने तो निश्चित सिर्फ इसी को माना है जैसा कि उसने कहा है- मौत का दिन मुयम्मन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती? बारात के दिन के लिए तो बाकायदा पोथी-पत्रा दिखाया जाता है, शुभ लग्न-मुहुर्त निकलवाया जाता है। बस इसी शुभ लग्न के चक्कर में साया भारी हो जाता है और सड़कें जाम हो जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस भारी सायों पर बेशक एडवाइजरी तो जारी नहीं करती, पर अक्सर लोगों को पता चल ही जाता है कि आज जाम लगेगा। क्यों जी? क्या कोई रैली है, कोई धार्मिक जुलूस निकलने वाला है। अरे आज पंद्रह हजार शादियां होंगी। मैरिज पैलेस नहीं मिल रहे, बैंडवाले, कैटर्स यहां तक कि घोड़ियां भी नहीं मिल रही। दिल्ली में खुशी का हाहाकार मच जाता है। ज्यादा खुशी हमेशा आंसू देती है। जबकि अर्थी पर तो कायदे से आंसू निकलने ही चाहिए। हालांकि अब तो सीलिंग पर भी निकल रहे हैं। इधर खून के आंसू रोने के अवसर काफी मिल रहे हैं। कभी नोटबंदी के लिए, कभी जीएसटी के लिए और कभी सीलिंग के लिए। पर अर्थी पर आंसू का तो खैर कायदा ही है। बस अभी तक वे बारातों की तरह थोक में नहीं निकलती थी, सो जाम भी नहीं लगता था। पर लगता है अब यह रिवायत टूट गई है। इधर दिल्ली में सीलिंग की इतनी अर्थियां निकली कि उन्होंने बारातों का भी रिकार्ड तोड़ दिया। अभी तक यह तो होता था कि सरकारों की हाय-हाय तो खूब होती थी। नेताओं के पुतले भी जलाए जाते थे। लेकिन जिस तरह से सीलिंग की अर्थियां निकली उससे तो यही साबित हुआ साहब कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। सीलिंग की अर्थी निकली तो बाजार बंद हो गए। वीरानी छा गई। अर्थी निकलती है तो चाहे कितना ही कम हो, पर एक दुख का भाव तो होता ही है, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए ही हो। पर सीलिंग की अर्थियां ऐसे निकल रही थी जैसे रोष की अभिव्यक्ति हो रही हो। पर साहब अगर दिल्ली में जाम ही लगना है तो फिर बारातों की वजह से ही लगे न, अर्थियों की वजह से क्यों लगे?

दिल्ली में चाहे बारात निकलें या अर्थी निकलें, जाम तो लगना ही होता है। हालांकि अभी तक होता यह आया था कि बारात का दिन तो निश्चित ही होता है। पर अर्थी का नहीं होता। जबकि शायर ने तो निश्चित सिर्फइसी को माना है जैसा कि उसने कहा है-मौत का दिन मुयम्मन है

फोटोग्राफी...

शुद्ध पानी व्यर्थ न बह जाए, इसलिए 2040 मीटर की ऊंचाई पर बनाया था यह रिजर्वायर

यह फोटो ऑस्ट्रिया में 2040 मीटर की ऊंचाई पर बने कपरून रिर्जवायर का है, जो यूरोप में शुद्ध जल का प्रमुख स्रोत में से एक है। यह मूलत: दो रिर्जवायर (वेज़रफाल्बो डेन एवं मूज़रबोडेन) से मि लकर बना है। ऑस्ट्रिया की कपरून वादी कभी केवल पर्वतीय जंगलों से जानी जाती थी, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वहां ये रिर्जवायर बनाए गए। पहले यह प्राकृतिक झील की तरह थे, लेकिन बाद में यहां व्यवस्थित निर्माण करके एल्प्स पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों की बर्फ से बहकर आने वाले पानी को संरक्षित किया गया। उसके पहले यह पानी व्यर्थ बह जाता था। आज यह जगह ऑस्ट्रिया में न केवल पर्यटन का आकर्षण है, बल्कि इसे इंजीनियरिंग के श्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है। सि तंबर 1955 में यहां 107 मीटर ऊंची दीवार वाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट तैयार किया गया, जिससे आधे देश का बिजली संकट दूर हुआ। ऑस्ट्रिया में मूज़रबोडेन रिर्जवायर बनाने की योजना 1920 के दशक की है। 1930 के दशक में उसका काम पूरा हुआ, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ही उसे पूरा किया जा सका। इसे वहां एल्प्स पर्वत श्रृंखला का बेस भी कहा जाता है। फरवरी से सितंबर तक स्थानीय आबादी यहां पर्यटकों का स्वागत करती है, शेष महीनों में यहां पहुंचना मुश्किल होता है। sonurai.com

जल संरक्षण के विषय

विश्व जल दिवस यानी पानी के वास्तविक मूल्य को समझने का दिन, पानी बचाने के संकल्प का दिन। पानी के महत्त्व को जानने का दिन और जल संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन। आंकड़े बताते हैं कि विश्व के 1 .6 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। पानी की इसी जंग को खत्म करने और जल संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में रियो डि जेनेरियो के अपने अधिवेशन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि विश्व के अनेक हिस्सों में पानी की भारी समस्या है और इसकी बर्बादी नहीं रोकी गई तो स्थिति और विकराल हो जाएगी क्योंकि भोजन की मांग और जलवायु परिवर्तन की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति जीवनदायी संपदा जल हमें एक चक्र के रूप में प्रदान करती है, हम भी इस चक्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। चक्र को गतिमान रखना हमारी जिम्मेदारी है, चक्र के थमने का अर्थ है; हमारे जीवन का थम जाना। प्रकृति के खजाने से हम जितना पानी लेते हैं, उसे वापस भी हमें ही लौटाना है। हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते अत:-प्राकृतिक संसाधनों को दूषित न होने दें और पानी को व्यर्थ न गंवाएं-यह पग्रलेना बहुत आवश्यक है। धरातल पर तीन चैथाई पानी होने के बाद भी पीने योग्य पानी एक सीमित मात्रा में ही है। उस सीमित मात्रा के पानी का इंसान ने अंधाधुध दोहन किया है। नदी, तालाबों और झरनों को पहले ही हम केमिकल की भेंट चढ़ा चुके हैं, जो बचा-खुचा है उसे अब हम अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। संसार इस समय जहां अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में व्यस्त है, वहीं पानी, खाद्य और ऊर्जा की पारस्परिक निर्भरता की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। जल के बिना न तो हमारी प्रतिष्ठा बनती है और न गरीबी से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी शुद्ध पानी तक पहुंच और सैनिटेशन यानी साफ-सफाई, संबंधी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुंचने में बहुतेरे देश अभी पीछे हैं। एक पीढ़ी से कुछ अधिक समय में दुनिया की आबादी के 60 प्रतिशत लोग कस्बों और शहरों में रहने लगेंगे और इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी विकासशील देशों में शहरों के अंदर उभरी मलिन बस्तियों और झोपड़पट्टी के रूप में होगी। जिन लोगों के घरों या नजदीक के किसी स्थान में पानी का नल उपलब्ध नहीं है, ऐसे शहरी बाशिंदों की संख्या विश्व परिदृश्य में पिछले दस वर्षो के दौरान लगभग ग्यारह करोड़ चालीस लाख तक पहुंच गई है, और साफ-सफाई की सुविधाओं से वंचित लोगों की तादाद तेरह करोड़ 40 लाख बताई जाती है। बीस प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्य और आर्थिक उत्पादकता पर पड़ा है । भारत में विश्व की लगभग 16 प्रतिशत आबादी निवास करती है, लेकिन उसके लिए मात्र 4 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। विकास के शुरुआती चरण में पानी का अधिकतर इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता था। मगर समय के साथ स्थिति बदलती गई और पानी के नये क्षेत्र-औद्योगिक व घरेलू-अहम होते गए। जल नीति के विश्लेषक सैंड्रा पोस्टल और एमी वाइकर्स ने पाया कि बर्बादी का एक बड़ा कारण यह है कि पानी सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। कई देशों में सरकारी सब्सिडी के कारण कीमत बेहद कम है। इससे लोगों को लगता है कि पानी बहुतायत में उपलब्ध है, जबकि हकीकत उलटी है। अगर सही ढंग से पानी का संरक्षण किया जाए और जितना हो सके पानी को बर्बाद करने से रोका जाए तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है ऐसी जागरूकता की, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों को भी पानी बचाना अपना धर्म समझें।

मुख्य कारोबार समाचार

टेलीसॉनिक नेटवर्क के अलग होने के मुद्दे पर NCLT पहुंचा एयरटेल

नयी दिल्ली। दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल और उसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टेलीसॉनिक नेटवर्क ने अपनी अलग होने की योजना को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि इसअलगाव के बाद टेलीसॉनिक एक स्वतंत्र फाइबर केबल कंपनी की तरह कारोबार करेगी। दोनों कंपनियों ने अपना पहला प्रस्ताव न्यायाधिकरण के सामने पेश कर इसके लिए अनुमति की मांगी थी, ताकि वह अपने हितधारकों, शेयरधारकों और ऋणे देने वालों की बैठक बुलाकर अनुमति ले सके। एनसीएलटी के अध्यक्ष एम. एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारतीय एयरटेल ने एक नवंबर 2017 को कहा था कि वह वह अपना आप्टिकल फाइबर व्यावसाय 5,650 करोड़ रुपये के मूल्य पर टेलिसोनिक नेटवर्क्स को हस्तांतरित कर देगी।

सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिए दिए 2,161 करोड़ रुपए

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडन ने रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च2020 तक के लिए 2,161.68 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) की यहां हुई बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना से रेशम का उत्पादन 2019-20 तक 38,500 टन करने का है जो 2016-17 में 30,348 टन था। एक ट्वीट में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस योजना का मकसद शोध एवं विकास, तकनीक उन्नयन और कौशल गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से रेशम उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना 2020 तक इस क्षेत्र में 85 लाख रोजागार को बढ़ाकर एक करोड़ करने में मदद करेगी।

पंजाब सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी किए 1,200 करोड़ रूपए

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भुगतान पूरा करने के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी किए। इनमें वह योजनाएं भी शामिल हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। साथ ही सरकार ने भरोसा दिलाया कि कोष की कमी को विकास के आगे आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सरकार ने 1,220.99 करोड़ रुपये जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी भुगतानों को निपटाने के काम को प्राथमिकता दें और राजकोषीय प्रबंधन का पालन करते हुए पर्याप्त कोष का उपयोग करें।

कनिष्क गोल्ड के डायरेक्टर भूपेश जैन, नीता जैन से CBI ने की पूछताछ, 824 करोड़ का है फ्रॉड

नई दिल्ली. करीब 824 करोड़ रुपए के एसबीआई फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स भूपेश जैन और नीता जैन से पूछताछ की। साथ ही सीबीआई ने कनिष्क गोल्ड के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ लूक-आउट सर्कुलर जारी कर दिया है।

प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाएगी सरकार, महंगी हो सकती है सीएनजी

नयी दिल्ली। सरकार घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम अगले सप्ताह बढ़ाकर इसके दो साल के उच्च स्तर पर कर सकती है। सरकार के इस कदम से सीएनजी महंगी होगी वहीं बिजली व यूरिया उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली अधिकतर प्राकृतिक गैस का दाम एक अप्रैल से बढाकर 3.06 डालर प्रति एमबीटीयू :प्रति इकाईः किया जाएगा जो कि इस समय 2.89 डालर है। अमेरिका, रूस व कनाडा जैसे गैस अधिशेष देशों के औसत मूल्य के आधार प्राकृतिक गैस के दाम हर छह महीने तय होते हैं। भारत अपनी आधी गैस आयात करता है जिसकी लागत उसकी घरेलू दर से दोगुने से भी अधिक है। सूत्रों ने कहा कि 3.06 डालर प्रति एमबीटीयू की दर एक अप्रैल से छह महीने के लिए लागू होगी। यह दर अप्रैल सितंबर 2016 के बाद की उच्चतम होगी जबकि घरेलू उत्पादों को इसी दर से भुगतान किया गया था। घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से जहां ओएनजीसी व रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी उत्पादक कंपनियों की आय बढ़ेगी वहीं इससे सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं जिसमें प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इससे यूरिया व बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। इससे पहले सरकार ने अक्तूबर 2017 से मार्च 2018 के लिए गैस कीमत को बढ़ाकर2.89 डालर प्रति एमबीटीयू किया था। यह दर पूर्व छह महीने के लिए2.48 डालर थी।

वैश्विक व्यापार 'युद्ध' छिड़ने की आशंका में सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका और यूरोपीय बाजारों में नुकसान से रीयल्टी, पूंजीगत सामान, प्रौद्योगिकी, वाहन तथा बैंकिंग शेयरों में उच्चस्तर पर मुनाफावसूली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज130 अंक टूट गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतेरी के बाद वैश्विक बाजारों में नरमी का रुख रहा, जिससे यहां भी धारणा प्रभावित हुई। बंबई शेयर बाजार का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 33,206.99 अंक पर मजबूती के रुख से खुलने के बाद 33,281.77 अंक के उच्चस्तर तक गया। बाद में यह नकारात्मक दायरे में आया और इसने 32,963.31 अंक का निचला स्तर भी छुआ। अंत में सेंसेक्स 129.91 अंक या 0.39 प्रतिशत के नुकसान से 33,006.27 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 40.50 अंक या 0.39 प्रतिशत के नुकसान से 10,114.75 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 10,207.85 से 10,105.40 अंक के दायरे में रहा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''फेडरल रिजर्व के कम आक्रामक रुख की वजह से बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला। हालांकि, व्यापार युद्ध की आशंकानये सिरे से उभरने के बाद यूरोपीय और एशियाई बाजारों के नकारात्मक रुख से यह लाभ थोड़े समय तक ही टिक पाया।''

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि चीन बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी अपने हितों की रक्षा में कदम उठाने की बात कही है। एनएसई बैंक निफ्टी में साप्ताहिक डेरिवेटिव निपटान की वजह से बैंकिंग शेयर दबाव में रहे। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और बैंक आफ बड़ौदा का शेयर2.62 प्रतिशत तक नीचे आया।

अन्य कंपनियों में विप्रो, एमएंडएम, मारुति सुजुकी, डॉ रेड्डीज, अडाणी पोर्ट, इन्फोसिस, बजाज आटो, एलएंडटी, टीसीएस, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकार्प, आईटीसी, टाटा स्टील और हिंद यूनिलीवर 2.32 प्रतिशत तक टूट गए। हालांकि, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा, एशियन पेंट और एनटीपीसी के शेयर2.45 प्रतिशत लाभ के साथ बंद हुए।

बीएसई स्मालकैप 1.05 प्रतिशत और मिडकैप 0.75 प्रतिशत नीचे आया। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.09 प्रतिशत, शांगहाए कम्पोजिट 0.53 प्रतिशत तथा सिंगापुर 0.65 प्रतिशत नुकसान में रहा। जापान का निक्की 0.99 प्रतिशत चढ़ गया। शुरूआती कारोबार में यूरोपीय बाजार नीचे चल रहे थे। इस बीच शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल शुद्ध रूप से 98.44 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 197.78 करोड़ रुपये की लिवाली की।

ट्रेनों में शुरू होगी POS के जरिए बिल सुविधा, अधिक दाम से मिलेगी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

ट्रेनों में सामान बेचने वालों द्वारा ज्यादा कीमत वसूले जाने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुये आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में प्वाइंट ऑफ सेल(पीओएस) उपकरण के जरिये बिलिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन(आईआरसीटीसी) की तरफ से एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से हाथ में पकड़े जाने वाले पीओएस उपकरण पेश किये जा रहे हैं। 26 ट्रेनों में 100 ऐसी मशीनों के साथ इसकी शुरूआत की जा रही है। फिलहाल बेंगलुरू-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस में पायलट आधार पर पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। बयान के मुताबिक, 'इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को प्रासंगिक सूचनाओं के बारे में जानकरी रखने में मदद मिलेगी बल्कि उनकी संतुष्टि के स्तर में भी सुधार होगा।'

एमसीएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का पहला पीतल वायदा

केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया ने बताया कि एमसीएक्स पर पीतल (ब्रास) वायदा कारोबार शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा मुरादाबाद शहर के कारोबारियों और इंडस्ट्री को होगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) ने आज विश्व स्तर पर पहली बार पीतल में वायदा कारोबार को लॉन्च कर दिया है। यह पीतल हितधारकों के जोखिमों को कम करने का काम करेगा। इसके लिए एक्सचेंज को सेबी से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। मेटल सेग्मेंट में यह 6वां मेटल होगा जिसमें वायदा कारोबार की सुविधा मिलेगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एक्सचेंज पर अब तक कॉपर, जिंक, निकेल, लेड और एल्युमिनियम में कारोबार हो रहा है। कब शुरू होगा पीतल का वायदा- देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज में 26 मार्च से ही पीतल का वायदा कारोबार शुरू हो जाएगा। इसमें ट्रेडिंग के लिए अप्रैल, मई और जून के अंत में तीन अनुबंध की पेशकश की जाएगी, जिसका लॉट साइज करीब एक टन का होगा।

एक्सचेंज की ओर से जारी की गई रिलीज में कहा गया कि पीतल का वायदा सिर्फ हितधारकों को एक संगठित और बेहतर मूल्य देने वाला मंच ही नहीं प्रदान करेगा बल्कि इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के बेंचमार्क मूल्य का उपयोग करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही वो अपने मूल्य के जोखिम को कम कर पाने में भी सक्षम होंगे। गौरतलब है कि एमसीएक्स पर पीतल वायदा अनिवार्य वितरण विकल्प वाला पहला नॉन-फेरस अनुबंध है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया ने बताया कि एमसीएक्स पर पीतल (ब्रास) वायदा कारोबार शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा मुरादाबाद शहर के कारोबारियों और इंडस्ट्री को होगा। मुरादाबाद देश में पीतल का सबसे बड़ा बाजार है। ब्रिटेन, अमेरिका,मिडिल ईस्ट एशिया, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों से पीतल का आयात मुरादाबाद से ही किया जाता है। मुरादाबाद में पीतल से जुड़ी करीब 600 एक्सपोर्ट यूनिट और 9000 इंडस्ट्रियां काम करती हैं। जैसा कि पीतल का इस्तेमाल मिक्सिंग के लिए किया जाता है, ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ऑटोमोबाइल पार्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केडिया ने कहा कि इसके बाद एमसीएक्स का बेस मैटल का बकेट पूरा हो जाएगा।

SC का RCom's की संपत्ति की बिक्री पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्ति को आर. जियो को बेचने पर यथास्थिति बनाये रखने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरिमन और न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आर- काम की संपत्ति की बिक्री पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गयी रोक हटाने से इंकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय संपत्ति की बिक्री पर उच्च न्यायालय की रोक के आदेश पर बैंकों के कंसोर्टियम और आर- काम की अपीलों पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने कल शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी। इस आदेश को बंबई उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। न्यायाधिकरण ने आर-काम की एकीकृत संपत्ति पर अपना दावा करने की एरिक्सन को अनुमति दे दी थी।

आर- काम पर भारतीय ऋणदाताओं का 42 हजार रूपए बकाया है। आर काम कंसालिडेटेड में अनिल अंबानी समूह की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकाम शामिल हैं। भारतीय ऋणदाताओं में स्टेट बैंक के अलावा बैंक आफ बडोदा, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, कार्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम ओर बार्कलेज बैंक इस संयुक्त ऋणदाता फोरम में शामिल हैं। इन्होंने आरकाम कंसालिडेटेड की संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से बिक्री की प्रक्रिया शुरू की थी। रिलायंस जियो इंफोकाम स्पेक्ट्रम, सेल टावर और1.78 लाख किलोमीटर की फाइबर लाइन सहित दूसरी सुविधाओं को17,300 करोड़ रूपए में खरीदने पर राजी हो गया था।

भारतीय भाषाओं में इंटरनेट की पेशकश बढ़ा सकती है 205 मिलियन नए यूजर्स: IAMAI

इंटरनेट इन इंडिक नामक शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी भारत में रहने वाले करीब 193 मिलियन लोग भारतीय भाषाओं की सामग्री तक अपनी पहुंच बना रहे हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अगर यूजर्स को उनकी पसंद की भाषा में इंटरनेट की पेशकश की जाए तो करीब 205 मिलियन ऐसे यूजर्स को इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है जिन्होंने अभी तक इंटरनेट पर लॉग इन नहीं किया है। यह जानकारी आईएएमएआई और कांतर आईएमआरबी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

इंटरनेट इन इंडिक नामक शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी भारत में रहने वाले करीब 193 मिलियन लोग भारतीय भाषाओं की सामग्री तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। जबकि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 141 मिलियन उपयोगकर्ता ऐसे हैं, जो ऑनलाइन इंडिक सामग्री का उपयोग करते हैं। देश में दिसंबर 2017 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का कुल आधार 481 मिलियन होने का अनुमान है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 'वर्तमान में, शहरी भारत में 160 मिलियन और ग्रामीण भारत में 732 मिलियन संभावित नए उपयोगकर्ता हैं। इनमें से 23 फीसद लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर उन्हें समाग्री इंडिक में उपलब्ध करवाई जाती है तो वो निकट भविष्य में इंटरनेट का उपभोग करने को तैयार हो सकते हैं।' इस रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'इसके प्रभाव में करीब अनुमानित रूप से 892 मिलियन संभावित नए यूजर्स हैं और अनुमानित रूप से 205 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं कि अगर भारत में इंडिक सामग्री को बढ़ावा दिया जाता है तो वो इंटरनेट पर आने को तैयार हैं।' इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महानगरों के अलावा अंग्रेजी का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, विशेषतौर पर समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बीच। भारत में इंटरनेट का दोहन तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कि इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयोग की भाषा के मुद्दे को फोकस नहीं किया जाता है।

यूरिया इकाइयों के लिए मौजूदा ऊर्जा नियम 2 साल तक रहेगा जारी: सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ने 14 यूरिया इकाइयों को सांकेतिक जुर्माने के साथ दो साल तक मौजूदा ऊर्जा नियमों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। ये इकाइयां 2015 की नीति के तहत नए ऊर्जा नियमों को पूरा नहीं कर पाई हैं। नयी यूरिया नीति 2015 के तहत 27 यूरिया इकाइयों को इस वित्त वर्ष के अंत तक ऊर्जा दक्षता नियमों को पूरा करना है। इनमें से सिर्फ11 यूरिया इकाइयां ही इस लक्ष्य को पूरा कर पाई हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति(सीसीईए) ने उर्वरक मंत्रालय के14 इकाइयों को सांकेतिक जुर्माने के साथ मौजूदा ऊर्जा नियमों को दो साल और जारी रखने की अनुमति दे दी। नाफ्था आधारित तीन यूरिया इकाइयों को भी गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध होने तक दो साल और के लिए मौजूदा ऊर्जा नियमों के तहत काम करने की अनुमति दी गई है। सीसीईए ने इसके साथ ही नयी यूरिया नीति 2015 के तहत 11 यूरिया इकाइयों के लिए अप्रैल, 2018 से नए ऊर्जा नियमों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। उर्वरक मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इससे सरकार को 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचाने में मदद मिलेगी।

डिश टीवी इंडिया और वीडियोकॉन डी2एच का विलय सौदा हुआ पूरा

विलय के बाद अब वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बन गई है

नई दिल्ली (एजेंसी)।

एक साल के लंबे इंतजार के बाद डीटीएच ऑपरेटर डिश इंडिया और वीडियोकॉन डीटूएच का विलय अब पूरा हो गया है। इस विलय के साथ ही यह देश का सबसे बड़ा डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा, जिसका यूजर बेस करीब 28 मिलियन का होगा। इस मर्जर के लिए दोनों ही कंपनियों के बोर्डों ने नवंबर 2016 में मंजूरी दे दी थी। यह विलय काफी सारी अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरा है जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, एनसीएलटी और भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा जनवरी महीने में डिश टीवी में अस्थायी तौर पर रुकावट भी देखी गई। डिश टीवी ने कहा कि वो हालिया दिवालियापन कार्यवाही के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है जिसे कंपनी के वीडियोकॉन डी2एच के साथ प्रस्तावित विलय के खिलाफ वीडियोकॉन ग्रुप की कुछ संस्थाओं की ओर से दायर किया गया था।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग की फाइलिंग में आज डिश टीवी इंडिया ने बताया कि उसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई (महाराष्ट्र में सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर एनसीएलटी की मंजूरी के बाद योजना के अनुसार कंपनी विलय के सभी चरणों को पूरा कर चुकी है और वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड का 22 मार्च 2018 को डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के साथ विलय हो गया है। इस विलय के बाद अब वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बन गई है।

फेसबुक और गूगल पर टैक्स लगाने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, पॉलिसी मेकर्स ने दिया सुझाव

नई दिल्ली (एजेंसी)।

यूरोपियन यूनियन (ईयू) के नीति निर्माताओं ने बुधवार को गूगल और फेसबुक जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों पर एक नए टैक्स लगाए जाने की पेशकश की है। हालांकि फिलहाल ईयू की ओर से ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। इस नए टैक्स के जरिए ईयू को 6.2 बिलियन डॉलर की कमाई हो सकती है। नीति निर्माताओं का मानना है कि यह कंपनियों की ओर से की जाने वाली कमाई पर एक वाजिब तरीके से कर लगाने का माध्यम है।

यह प्रस्ताव उन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा देगा जो डिजिटल कारोबार करती हैं

और उनके पास भारी तादात में यूजर्स और कस्टमर्स हैं। जबकि इससे उन देशों को फायदा होगा जिनको इनसे कम राजस्व हासिल होता है। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कई दौरों की स्वीकृति से होकर गुजरना होगा और यह यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव को बढ़ाने का काम करेगा।

यूरोपीय संघ के शीर्ष आर्थिक और कर अधिकारी पियरे मॉस्कोविसी ने बताया, 'डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्थाओं को उलटकर रख दिया है। आपका बस एक क्लिक वाणिज्यिक लेनदेन की पूरी श्रृंखला को ट्रिगर करता है। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में नकदी की कमाई होती है। यह कानूनी खामी अब स्वीकार्य नहीं है।'

क्या है प्रस्ताव: ईयू की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि उन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व पर 3 फीसद का टैक्स लगाया जाएगा, जहां उपयोगकर्ता की जानकारी कंपनियों को पैसा बनाने में मदद करती है। गूगल को अपने लक्षित विज्ञापन से होने वाली कमाई पर, फेसबुक को यूजर्स की जानकारी की बिक्री के लिए और अमेजन को उस मार्केटप्लेस फीस पर कर देना होगा जिसे वो एक कस्टमर पर दूसरे को बिक्री करने हेतु वसूलता है। इस प्रस्ताव के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर ईयू के नीति निर्माताओं ने कहा कि ऐसा निष्पक्षता के लिए किया जाना है। यूरोप में जो भी कंपनियां डिजिटल कारोबार में हैं वो 9.5 फीसद के कर का भुगतान करती हैं, जबकि जो कंपनियां परंपरागत बिजनेस मॉडल वाली हैं उन्हें 23.2 फीसद का कर भुगतान करना होता है।

तेल और गैस के 55 ब्लॉक की बिडिंग डेट में हुआ विस्तार, अब आखिरी तारीख 2 मई

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार ने बड़े पैमाने पर तेल और गैस ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब बिडिंग की आखिरी तारीख 2 मई निर्धारित की गई है। तेल की खोज के लिए 55 ब्लॉकों की नीलामी प्रस्तावित है और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत मूल रूप से इस बिडिंग को 3 अप्रैल को खत्म होना था। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की ओर से इस संबंध में एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया, 'सावधान! ओएएलपी के पहले दौर की बिक्री के लिए बिड सबमिशन की तारीख को बढ़ाकर 2 मई 2018 कर दिया गया है।' हालांकि इस विस्तार की कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आ पाई है। डीजीएच जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक सहायक इकाई है वर्तमान में ओएएलपी में उस बोली दौर के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित कर रही है, जिसे नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईपीएल) के तहत आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल जुलाई में अन्वेषण के तहत देश में खनन के अंतर्गत आने वाले लगभग 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी पसंद के ब्लॉक को चुनने की अनुमति दी थी। इस नीति के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) रखने की अनुमति है जो वर्तमान में किसी भी उत्पादन या अन्वेषण लाइसेंस के तहत नहीं है।

> तेल और गैस के लिए 55 ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिडिंग डेट में एक महीने का विस्तार दे दिया गया है।

छठ –पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा

महापर्व के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है

सूरत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिंगणपूर कम कोजवे तापी नदी के तट पर चैत्री छठ सूर्य उपासना का पर्व धूमधाम से मनाया जायेगा। पूर्वांध प्रांतो में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला छठ –पूजा का महापर्व के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। बिहार विकास मंडल के तत्वाधान में मनपा के सहयोग से छठ–पूजा हर वर्ष मनाया जाता है। यह यूपी और बिहार तक ही सिमित था। लेकिन उतर भारत के लोग जहां भी रहते है। इस पर्व को धूमधाम से मनाते है। महिलाए निर्जल रहकर व्रत करती है। रात भर प्रतीक्षा के बाद सूर्य देव को अर्ध अर्पण कर व्रत का समापन किया जायेगा। इस आयोजन में चेता के संगीत गायक सत्येंद्र रसिया एवं नृत्य गायिका पायल के साथ छठ पूजा मनाने का आयोजन किया गया है। पिछले नव वषी से बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव इस भगीरथ कार्य को धूमधाम से मनाने एवं पूर्वीत्तर राज्यों के प्रवासियों को अपना पूरा योगदान दे रहे है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर तापी तट पर मिटटी की प्रतिमा बनाकर देवी का आह्वान किया जायेगा। तीन दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में महिलाए पिछले कई दिन से तैयारी कर रही है। 23 मार्च को शाम के समय डूबते सूर्य को अर्ध ?य अर्पण किया जाएगा। रात के प्रतीक्षा के बाद सूर्यदेव को अर्ध अर्पण कर व्रत का समापन किया जायेगा। इस चैत्री छठ पूजा में चार से पांच हजार की जनमेदिनी उपस्थित रहेगी। सूरत मनपा का सहयोग रहेगा। नितिन भजिया वाला के नेतृत्व में तापी शुद्धिकरण अभियान में जुड़ने का भी आव्हान किया गया है। कोजवे के तट पर जलकुंभी का सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार विकास मंडल के कार्यकर्त्ता एवं पदाधिकारीगण का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। बाके बिहारी सिंह, कृष्णा सोरसिया ,नंदकुमार पंडित, मनोज यादव , रामधारसिह,दिनेश गुप्ता ,राजदेव यादव ,सुरेंद्र शर्मा ,दीनानाथ चौरसिया ,योगेंद्र शर्मा, सत्येंद्र चौरसिया ,जितेंद्र यादव ,वकिल चौरसिया ,राकेश गुप्ता, पदवारी चौरसिया, बलिराम यादव ,दीनानाथ यादव और ओमप्रकाश यादव के सहयोग से तापी तट वियर –कम कोजवे पर धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाएगी। बिहार विकास मंडल के तत्वाधान में छठ–पूजा का आयोजन किया गया है। शिंगणपूर कम –कोजवे तापी तट पर सभी तैयारियां हो चुकी है। मिटटी की प्रतिमा पथवारी की व्यवस्था और स्टेज को अंतिम रूप देते मंडल के कार्यकर्त्ता।

एयरपोर्ट के पीएसआई पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला

सूरत। शहर के अमरोली में एयरपोर्ट के पीएसआई पर देर रात को असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा अपशब्द बोलने पर पीएसाई ने टोका तो उस पर हमला कर दिया। जबकि इस घटना को लेकर अमरोली पुलिस में हत्या करने के प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरोली क्षेत्र स्थित रादाकृष्णा होटल पर गत रात्रि को एयर पोर्ट के पीएसआई केडी रावल खाना खाने गए थे। वहां कुछ असामाजिक तत्व अपशबदों का प्रयोग कर रहे थे।

सूरत। वेड रोड पुलिस चौकी के समक्ष सड़क खस्ताहाल होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालिका के अधिकारियो ने एक माह पूर्व सड़क पर डामरीकरण का भरोसा दिलाया था। लेकिन.रोड का कार्य आज दिन तक नहीं हुआ। सड़क के सामने प्रतिष्ठानों में उड़ती धूल से सभी व्यापारी आहत है। दरअसल ,दररोज वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे है। वेडरोड के व्यापारियो ने सड़क का निर्माण करने की मनपा से मांग की है।

सूरत। सहारा दरवाजा पर बीआरटीएस के रूट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए रोड को संकडा किया गया है। रात दिन वाहनों के आवाजाही से भरचक रहने वाला सहारा दरवाजा पर दररोज ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिलता है। निर्माणाधीन बीआरटीएस के कारण शिवाजी की प्रतिमा के पास दररोज जाम लगा ही रहेगा ,जहा तक रोड पर पतरे के छेड़ नहीं हटाए जाते है। तस्वीर –कांतिलाल मांडोत

प्राइमस से जले अमरोली के युवक की इलाज के दौरान मौत

सूरत। अमरोली क्षेत्र के छापराभाठा में रहने वाला युवक खाना बनाते समय प्राइमस भभकने से झुलस गया था। जिसको गंभीर हालत में स्मीमेर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापराभाठा वीसगाला मोहल्ला में रहने वाले पवन पन्नालाल शर्मा (20 वर्ष) गत रोज प्राइमस पर खाना बना रहे थे। उसी समय अचानक प्राइमस भभकने से उनके शरीर का काफी हिस्सा झुलस जाने से इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती किया गया था।

श्री गुर्जर क्षत्रिय समाज एवं विकसित जाति कल्याण विभाग की ओर से समाज शिक्षण शिविर 25 को

सूरत। श्री गुर्जर क्षत्रिय समाज एवं विकसित जाति कल्याण विभाग की ओर से आगामी 25 मार्च 2018 को श्री गुर्जर क्षत्रिय समाज भवन, रांदेर रोड, मेरूलक्ष्मी मंदिर के सामने सायं पांच बजे गुजरात पछात वर्ग विकास निगम के अध्यक्ष नरेन्द्र भाई सोलंकी की अध्यक्षता में समाज शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में निगम की योजनाओं, विकसित जाति कल्याण खाता की योजनाएं, सात फेरा समूह लगन योजना कक्षा एक से बारह में जिला में क्रमांकित तेजस्वी छात्रों को ईमान वितरण किया जाएगा। इस प्रसंग दौरान शहर भाजपा प्रमुख नितिन भाई भजियावाला, विधायक पूर्णेश मोदी तथा अरविंद राणा, पूर्व मेयर निरंजन भाई झांझमेरा, पूर्व जिला नायब नियामक विकसित जाति के आर बी गोहिल तथा कॉर्पोरेटर जस्सू बेन राठौड उपस्थित रहेंगे।

इज ऑफ डुईंग बिजनेस एक्ट 2017 के तहत बैठक

सूरत। आम की सीजन शुरू होने में अभी समय है। शहर में हर गली के नुक्क्ड़ पर आम रस की लारिया देखने को मिल रही है। केमिकल युक्त आम दस रूपये का एक ग्लास धड़ल्ले से बिक रहा है। आम अभी बाजार में नहीं आया है। आम का दाम करीब दो हजार के आसपास पेटी का भाव है ,जबकि बदाम आम के नाम से बिकने वाले आम रस लोगो के सेहत के लिए खतरनाक है। महानगरपालिका इस तरफ ध्यान देगी। तस्वीर–कांतिलाल मांडोत

सूरत। गुजरात में व्यापार–उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सृजित इज ऑफ डुईंग बिजनेस एक्ट –– 2017 के संदर्भ में जिला कलेक्टर महेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में जिला सेवा सदन में विविध विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिसमें उद्योग कर्ताओं को सिंगल विंडो क्लीयरिंस उपलब्ध करवाने के लिए सरल प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा उद्योगों को गति मिले, इस प्रकार के प्रयास किये जाने के बारे में विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में कलेक्टर महेन्द्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में तमाम विभागों को लेकर नई ई–गवर्नेंस की पहल के अन्तर्गत इज ऑफ डुईंग बिजनेस एक्ट 2017 ईओडीबी अमल में आया है। जिसमें इन्वेस्टर्स फेसिलिटेशन पोर्टल आईएफपी पर से लायसेन्स, औद्योगिक परवानगी, ई–पेमेन्ट जैसे साठ प्रकार की अर्जियां आईएफपी पोर्टल पर ऑन लाईन हो सकती हैं। राज्य सरकार ईओबीडी द्वारा उद्योगों के बीच इण्डस्ट्रियल फ्रेडली वातावरण बनाकर आसानी से उद्योग करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है। उद्योगों के बीच परस्पर स्पर्धात्मकता बरकरार रखने लिए और अधिक से अधिक रोजगारी निर्माण के लिए बिजनेस संबंधी कोशिश संभव हो सके, उतना सरल बनाने के लिए जिला का समूचा तंत्र कटिबद्ध है।

इस प्रसंग के दौरान अतिरिक्त निवासी कलेक्टर संजय वसावा सहित विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कापोद्रा में जहर गटक कर युवक ने दी जान

सूरत। कापोद्रा के नाना वराछा तापी दर्शन सोसाइटी में रहने वाला युवक किसी अज्ञात कारण से जहर गटक लिया जिसे इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया।

घटना के संदर्भ में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाना वराछा के तापी दर्शन सोसाइटी विभाग–1, घर नं. 12 का निवासी सतीशभाई वामनराव तांडे (32 वर्ष) ने गत रोज किसी अज्ञात कारण से जहरीली दवा पी ली। जिसे इलाज के लिए उसके परिजन स्मीमेर अस्पताल में ले गए। जहां सतीशभाई को मृत घोषित कर दिया। कापोद्रा पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

अडाजण में भारती रेजीडेंसी के एक फ्लैट से 19.37 लाख की चोरी

सूरत। अडाजण एलपी सवाणी स्कूल के पास भारती रेजीडेंसी के फ्लैट से 19.37 लाख का माल सामान चोरी करके चोरों को फरार हो जाने की रिपोर्ट अडाजण पुलिस में दर्ज कराई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अडाजण गौरव पथ रोड एलपी सवाणी स्कूल के पास भारती रेजीडेंसी फ्लैट नं. बी–1204 में रहने वाले अजयप्रकाश मधुसूदन नारायण किसी काम से बाहर गए थे। उसी दौरान 7 फरवरी से 12 मार्च के दौरान कोई चोर उनके घर में प्रवेश करके पलंग के अंदर रखे गए सूटकेस तथा पर्स में से सोने के जेवर करीब 540 ग्राम (कीमत–10,80,000 रुपए) और चांदी के वर्तन और जेवर (कीमत–76,250 रुपए) डायमंड के जेवर 7,50,000 रुपए, मोती के सेट 6 हजार रुपए, 25 हजार रुए नकद सहित कुल 1937250 रुपए का माल चोरी करके फरार हो गया। घटना के संदर्भ में अजयभाई ने अडाजण पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को आज देंगी अर्घ्य

सूरत। बिहार विकास मंडल की ओर से चैत्र नवरात्री के छठवें दिन मनाए जाने वाले छठ पर्व का आयोजन वियर कोजवे तापी नदी के तट पर किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य के हिंदूओं का अकेला पर्व है। यह तीन दिन तक चलने वाला पर्व है। यह पर्व नहाय खाय से शुरू होता है। इसमें व्रतियों द्वारा पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद पूरी रात प्रतिक्षा करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपेन पुत्र की लम्बी उम्र की कामना भगवान सूर्य से करती है। सूरत शहर में बसे लाखों बिहार, झारखंड ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी शुक्रवार को तापी तट सहित शहर के अन्य इलाके के जलाशयों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देगी। पूरी रात भगवान सूर्य को उगने की प्रतिक्षा करने के बाद शनिवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे कर व्रत का पारण करेंगी।

बिहार विकास मंडल की ओर से चैता गीत गायक सत्येन्द्र रसिया और नृत्य गायिका पायल अपने स्वर लहरियों की प्रस्तुति देगी। इस आशय की जानकारी मंडल अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव ने दी है।

कामरेज तहसील के स्वास्थ्य केन्द्र में कुपोषण के खिलाफ वर्कशॉप

सूरत। कुपोषण पर नकेल कसने के लिए कामरेज तहसील के स्वास्थ्य केन्द्र में कुपोषण के खिलाफ वर्कशॉप का आयोजन किया गया। नेशनल आर्यन प्लस इनिसेटिव मिशन शक्ति के रूप में कायक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में ग्राम्य स्तर पर लोग जागृत के लिए सूरत जिला विकास अधिकारी के.राजेश तथा सूरत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हंसमुख चौधरी व अन्य महानुभाव की उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्कशॉप पर आयोजन किया गया।

विद्यार्थियों से भरी स्कूल रिक्शा एस टी बस में घुसी, 8 से अधिक घायल

सूरत। लाजपोर के पास विद्यार्थियों से भरी स्कूल रिक्शा एस टी बस के पिछले हिस्से में घुस गई। जिससे रिक्षा में बैठे 8 से अधिक विद्यार्थी घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को समीप के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है।

लाजपोर क्षेत्र के कपलेठा गांव के समीप एमडी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की रिक्शाा विद्यार्थियों को लेकर जा रही थी उसी समय रिक्शा चालक अपना संतुलन खो दिया और रिक्शा सामने जा रही एसटी बस के पिछले हिस्से में जा घुसी। इस दुर्घटना में रिक्शा में सवार 8 से अधिक छात्र घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए समीप के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। जबकि रिक्शा चालक को गंभीर चोट आने से उसकी हालत नाजुक होने की जानकारी मिली है।

भाजपा के 39वें स्थापना दिवस पर 'भाजपा बूथ पदयात्रा' का आयोजन

अहमदाबाद। भाजपा ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर आगामी 6 अप्रैलको 'भाजपा बूथ पदयात्रा' का आयोजन किया है। गुजरात प्रदेश भाजपा की आज हुई बैठक में यह फैसला किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भरत पंड्या ने बताया कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय कमलम में गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतु वाघाणी की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन महासचिव भीखूभाई दलसाणिया, प्रदेश महासचिव भरतसिंह परमार, केसी पटेल, शब्दशरण ब्रह्मभट्ट की उपस्थिति में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि आगामी 6 अप्रैल 2018 को भाजपा का 39वां स्थापना दिवस है और यह दिन भाजपा की विचार यात्रा और विकास यात्रा का ऐतिहासिक दिन है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर–2 के पीछे, उधना, जिला–सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :– सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com